भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 668
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2026

आंध्र प्रदेश के पीवीटीजी गांवों में मोबाइल टावर

668. डॉ. सी.एम. रमेश:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने पीएम जनमन के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) पीवीटीजी जनजातीय गांवों में 1010 बस्तियों में 95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मोबाइल टावरों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में शामिल की गई बस्तियों का ब्यौरा क्या है जहां 8,500 से अधिक पीवीटीजी जनजातीय आबादी है; और

(ग) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) कार्यक्रम के तहत पहचाने गए 4,543 पीवीटीजी गांवों/बस्तियों में से 3,231 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) गांवों/बस्तियों को 4जी मोबाइल कवरेज प्राप्त हुआ है। इन गांवों/बस्तियों को डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित 4जी मोबाइल परियोजनाओं के तहत कवर किया गया था, और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य में, चिन्हित गांवों/बस्तियों में से, 1,409 पीवीटीजी बस्तियों/गांवों को 4जी मोबाइल कवरेज मिला है, जिनमें से 9 अनकापल्ली जिले में हैं।

*****